भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 14**

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**झीलों, झरनों और हिमनदों का तेजी से पिघलना**

**14 . श्री भगत सिंह कोश्यारी :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलवायु परिवर्तन और विश्व के तापमान में वृद्धि होने के कारण मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में झीलें, झरने और हिमनद बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केदारनाथ में हुई तबाही का कारण भी हिमनदों का पिघलना था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं/ किये जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कराए गए अध्ययनों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों में हिमनद भिन्न-भिन्न गति से पिघल रहे हैं । इन निष्कर्षों के अनुसार हिमनदों का घटना, प्राकृतिक चक्रीय प्रक्रियाओं और अन्य घटकों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक तापन भी शामिल हैं, के परिणामस्वरूप हो सकता है ।

(ख) और (ग) केदारनाथ क्षेत्र में विनाश मुख्य रूप से हिमनदो के पिघलने के कारण नहीं है । अत्यधिक वर्षा अत्यधिक बर्फ का पिघलना और उर्ध्वधारा में चौराबारी झील में दरार पड़ने के मिल-जुले प्रभाव से अत्यधिक मलबे सहित पानी के तेज प्रवाह ने समूची घाटी को तहस-नहस कर दिया । संपूर्ण आवाह क्षेत्र में भारी वर्षा ने अधोधाराओं में बाढ़ की व्यापकता में अत्यधिक वृद्धि कर दी ।

सरकार भारत के विकास पथ की पारिस्थितिकीय सततता में वृद्धि करने और देश के सभी भागों में जलवायु परिवर्तन के निराकरण करने की दृष्टि से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) को कार्यान्वित कर रही है । एनएपीसीसी में अन्य बातों के साथ-साथ आठ राष्ट्रीय मिशन समावेशित हैं जिनमें हिमालयी पारि-प्रणाली की सततता हेतु राष्ट्रीय मिशन शामिल है जिसका उद्देश्य हिमालयी हिमनदों का अवलोकन और मानीटरन हेतु प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है । इसके अतिरिक्त देश में बृहत हिमनद अनुसंधान करने के लिए हिमालयी भू-विज्ञान संबंधी अनुसंधान केन्द्र वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान देहरादून में स्थापित किया गया है । इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में स्थित राज्यों सहित सभी राज्यों को विशिष्ट जलवायु परिवर्तन मुद्दों के निराकरण हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना को तैयार करने के लिए परामर्श दिया गया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*